मोदी के तेज राज में ई एस आई मेडिकल कॉलेज की कछुआ गति

फ़रीदाबाद (म.मो.) मोदी जी की केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाला ई एस आई निगम मज़दूरों के साथ क्रूर मज़ाक करने में जुटा है। मासिक 15000 तक वेतन पाने वाले मज़दूरों से उनके वेतन का साढे छः प्रतिशत वसूलने वाले इस निगम के जिम्मे इन मज़दूरों एवं इनके परिवारों की चिकित्सा कराना है, जिसका ठेका इसने हरियाणा सरकार को दे रखा है। हरियाणा सरकार की अकर्मण्यता एवं हरामखोरी के चलते यह व्यवस्था पूरी तरह से फ्लॉप होती जा रही थी। इसके 300 बिस्तरों वाले (एन एच 3) अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या 70 से घट कर मात्र 17 रह गयी थी। इसी अनुपात में अन्य स्टाफ़ भी लुप्त होता जा रहा था। 300 की क्षमता वाले इस अस्पताल में मात्र 120 मरीज ही दाखिल रहने लगे।

इस दुर्दशा को देखते हुए ई एस आई निगम ने वर्ष 2009 में यहां मेडिकल कॉलेज एवं 500 बिस्तरों का अस्पताल बना कर खुद चलाने की आधारशिला रखी। करीब 4 वर्ष बाद, सितम्बर 2013 में ई एस आई निगम ने इस अस्पताल को भी अपने हाथ में लेकर चलाने का नाटक शुरू किया। निगम ने सबसे पहला काम तो उन 36 पैरामेडिकल स्टाफ़ को निकाल बाहर करने का किया जिनकी मदद से 17 डॉक्टर इस अस्पताल को जैसे तैसे घसीट रहे थे। इन 36 कर्मचारियों का दोष यह था कि ये ठेकेदारी में काम कर रहे थे, इन्हें हरियाणा सरकार ने नियमित भर्ती नहीं किया था। उस वक्त निगम का तर्क था कि ठेकेदारी में कर्मचारी नहीं रखते। परिणाम यह हुआ कि वार्डों में पहले जहां 120 मरीज़ दाखिल रहते थे घट कर 40 रह गये। बाहरी मरीज़ (ओ पी डी) जो प्रतिदिन 1400-1500 आते थे घट कर 300 रह गये।

नतीजा यह कि ई एस आई निगम द्वारा अस्पताल को अपने हाथ में लिये जाने के 15 माह बाद आज यहां की स्थिति पहले से बद्तर ही है। आज भी यहां ओ पी डी में 700 से ज़्यादा मरीज नहीं आते और वार्डों में भी औसतन 80-90 मरीज़ ही दाखिल रहते हैं।

इस तरह का कुप्रबन्धन एवं हरामखोरी कांग्रेसी मनमोहन राज में होनी तो समझ में आती है परन्तु भाजपाई मोदी सरकार के राज में भी होनी समझ में नहीं आती। मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, उनकी सुनता कोई नहीं था, वे फ़ैसले नहीं कर पाते थे आदि-आदि। परन्तु मोदी तो सारा दिन बोलते ही रहते हैं, सुनते भी हैं, गतिमान भी बहुत हैं, फ़ैसले भी खूब लेते हैं, 'सबका साथ सबका विकास' का नारा भी देते हैं; परन्तु धरातल पर वही सब हो रहा है जो पहली सरकार के जमाने में हो रहा था।

गत 14 माह में निगम द्वारा इस अस्पताल में कुल 68 डॉक्टर (फेकल्टी, एस आर, जे आर, जी डी एम ओ आदि) रखे गये हैं जबकि 65 डॉक्टरों की अभी भी कमी है। नर्सिंग स्टाफ़ में अभी भी 84 की कमी है, जो 96 रखी गयी हैं उनमें से 25 तो पहले से ही (हरियाणा सरकार द्वारा) रखी हुई थी। निगम ने जो 70 भर्ती की हैं वे ठेकेदारी में हैं। अन्य पैरामेडिकल स्टाफ़ में 148 की कमी है जो 141 रखे हैं उनमें से 97 ठेकेदारी में है। सबसे अधिक बुरा हाल मिनिस्टीरियल (दफ़्तरी) स्टाफ़ का है। जरूरत है 142 की और मौजूद है केवल 17। यानी अभी 125 छोटे बड़े बाबुओं की कमी है।

बताने की जरूरत नहीं कि किसी भी अस्पताल को अकेले डॉक्टर ही नहीं चलाते, बल्कि हर तरह के स्टाफ़ का महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि देश में बाबुओं अथवा अन्य किसी स्टाफ़ की उपलब्धता नहीं है। कुछ खास किस्म के डॉक्टरों तथा तकनीकी लोगों को छोड़कर बाकी सभी तरह का स्टाफ़ खूब उपलब्ध है। हर तरह के प्रशिक्षित लोग काम की तलाश में मारे-मारे फ़िर रहे हैं और एक यह ई एस आई निगम का अस्पताल है जिसे भर्ती करने में मौत पड़ रही है। यूं तो ई एस आई के गुड़गांव तथा फ़रीदाबाद के अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ़ की भर्ती का काम गुड़गांव की चिकित्सा अधीक्षक (एम्स) को दिया हुआ है। उन्होंने इसके लिये दिसम्बर 2012 में भर्ती हेतु आवेदन भी मांगे थे। करीब 17000 लोगों ने बैंक ड्राफ्ट सहित आवेदन भी किये थे। परन्तु एक माह बाद ही ई एस आई निगम मुख्यालय ने इस भर्ती पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि अभी क्या जल्दी है, जब अस्पताल बन जायेगा तब देख लेंगे। जो अभी तक देख ही रहे हैं।

हां सुरक्षा के नाम पर निर्धारित 50 तैनातियों में से एक भी रिक्त नहीं है। बेशक ठेकेदारी में ही सही तमाम 50 नियुक्तियां कर दी हैं। इसके चलते नीली वर्दीधारी हाथ में डंडा लिये जगह-जगह खड़े मिल जायेंगे। डॉक्टर या अन्य स्टाफ़ हो न हो ये जरूर हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। सुरक्षा के नाम पर आये दिन इनका मरीज़ों से बराबर झगड़ा होता है। दरअसल मरीज़ों की लम्बी-लम्बी लाइनों को निपटाने के लिये पर्याप्त स्टाफ़ लगाने के बजाय निगम ने इन लठैतों को भर्ती कर लिया है।

इससे भी बुरा हाल उन चिकित्सीय उपकरणों एवं औजारों का है जिनके बिना डॉक्टर अपनी डॉक्टरी नहीं कर सकते। इन उपकरणों की खरीदारी के लिये करोड़ों रुपया पड़ा है लेकिन खरीदारी पर्याप्त मात्रा में नहीं की जा रही है। उपकरणों की कमी के चलते एक तो ऊंचे-ऊंचे वेतनों पर भर्ती किये गये विशेषज्ञ डॉक्टर ठाली बैठे बोर हो रहे हैं दूसरी ओर मरीज़ों को निजी अस्पतालों में भेजा जा रहा है। इससे जहां एक ओर मरीज़ परेशान होते हैं वहीं निगम को भी सालाना 30 से 40 करोड़ का चूना लग रहा है। हालात को देख कर तो ऐसा भी लगता है कि निगम अधिकारियों की निजी अस्पतालों से सांठ-गांठ चल रही है और उनके व्यापार को बढावा देने की नीयत से ही जानबूझ कर ई एस आई के अस्पताल को नहीं चलाया जा रहा।

ई एस आई अस्पतालों में नियम विरुद्ध ठेकेदारी प्रथा

ई एस आई निगम द्वारा संचालित गुड़गांव के दो तथा फ़रीदाबाद के एक अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ़ की बरसों से चली आ रही भारी कमी को दूर करने के लिये नियमित भर्ती की अपेक्षा ठेकेदारी पर स्टाफ़ को रखा जा रहा है। जबकि निगम के नियमों के अनुसार इस तरह की ठेकेदारी पर स्टाफ़ को नहीं रखा जा सकता। केवल नियमित भर्ती का प्रावधान है।

ठेकेदारी में स्टाफ़ रखने के पीछे निगम का उद्देश्य पैसा बचाकर उनका शोषण करना है। जिस स्टाफ़ को वेतनमान के अनुसार 30 000 मासिक देने पड़ते हैं, ठेकेदारी में वही स्टाफ़ दस से बारह हज़ार में पड़ जाता है। इसमें ठेकेदार का जो कमीशन बनता है वह भी स्टाफ़ के इसी वेतन से कटता है। इसके अलावा श्रम कानूनों का उल्लंघन करके ठेकेदार जो शोषण करता है वह अलग से। श्रमिकों के वेतन से काटा गया भविष्य निधि व ई एस आई का पैसा ठेकेदारों द्वारा हड़पने की शिकायतें भी कम नहीं आती।

इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठेकेदारी में रखे गये स्टाफ़ का अपने संस्थान से कोई जुड़ाव नहीं होता। वह नियमित नौकरी की तलाश में जुटा रहकर केवल टाइम-पास करने को नौकरी करता है। संस्थान की बहुमूल्य मशीनों एवं उपकरणों आदि के प्रति भी उसका ज़िम्मेदाराना भाव नहीं होता। कोई चीज़ बिगड़ती है तो बिगड़े, टूटती है तो टूटे उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा? नौकरी से निकाले जाने का उसे कोई भय इसलिये नहीं होता कि वह इससे पहले ही असन्तुष्ट होता है। ऐसा स्टाफ़ मरीज़ों के प्रति क्या आत्मीयता एवं सद्भावना रख सकता है?

"कामगारों का हित और उनकी सामाजिक सुरक्षा परम आवश्यक है"-केन्द्रीय श्रम मन्त्री

नर्द दिल्ली (म.मो.) बंडारू दत्तात्रेय केन्द्रीय मंत्री श्रम और रोजगार, ने दिनांक 18/11/2014 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली के आपने प्रथम दौरे पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.) के कार्यपद्धति की समीक्षा की। दत्तात्रेय ने निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। ए.के. अग्रवाल, महानिदेशक, निगम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्रीजी को क.रा.बी. योजना के मुख्य विशेषताओं से अवगत कराया।

क.रा.बी. निगम के अधिकारियों को संबोधित करते समय दत्तात्रेय ने उन्हें कामगारों के हित और उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखने के लिये कहा। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि वे कामगार वर्ग के रोगियों का उपचार इस प्रकार करें कि वे सहज महसूस करें। उन्होंने निगम प्रबंधन को क.रा.बी. अस्पतालों में अति विशिष्टता उपचार की अपलब्धता की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया। निगम की व्याप्ति के पहलुओं की प्रशंसा करते समय उन्होंने कहा कि भारत के 93 प्रतिशत कर्मचारी जो कि असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं, वे क.रा.बी. निगम के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। मंत्री जी ने निगम द्वारा वर्तमान में संचारित परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा की भी प्रशंसा की। इसके अतरिक्त उन्होंने निर्देश दिया कि विशेषकर निम्नतर स्तर पर कार्यक्षमता में वृद्धि करके लक्ष्यों का प्राप्त किया जाए। दत्तात्रेय ने कहा कि श्रम और रोजग़ार मंत्रालय एक संवेदनशील मंत्रालय है तथा इस प्रकार के विभाग में कार्य करके सबको गर्व महसूस करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे बीमाकृत व्यक्तियों के कार्य 'सेवाभाव' से करें। उन्होंने अधिकारियों से श्रम-समर्थक अभिवृत्ति रखने तथा जनता की धारणा को परिवर्तित कर अपने संगठन की अच्छी छवि बनाने का भी आग्रह किया।

नवनियुक्त श्रम मंत्री ने निगम के पहले दौरे में वहां तैनात उच्चाधिकारियों के निकम्मेपन तथा मज़दूर विरोधी कारनामों के लिये उनकी खिचाई करने की बजाय उन्हें जो शाबाशी दी है, उससे उनकी हरमखोरी और भी बढेगी; जो अफ़सरशाही मज़दूरों के प्रति पहले से ही असंवेदनशील है अब और भी क्रूर हो जायेगी। यदि मंत्री महोदय स्वयं मज़दूरों के प्रति थोड़े से भी संवेदनशील हैं तो उन्हें इन अफ़सरों से पूछना चाहिये कि पिछले 5 साल से फ़रीदाबाद में अस्पताल बनाने के नाम पर क्या ड्रेमेबाज़ी करते आ रहे हैं। इसके लिये ज़िम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध उन्हें कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

नेहरू कॉलेज में रोल नम्बर वितरण बदइन्तज़ामी का एक नमूना

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 20 नवम्बर से प्रथम छमाही की परीक्षा शुरू होनी थी। इसके लिये एम डी यू रोहतक ने छात्रों के रोल नम्बर भेजे 18 नवम्बर को। छात्र परीक्षा की तैयारी छोड़ कर रोल नम्बर लेने की होड़ में जुटे। कॉलेज प्रशासन ने अपनी ओर बेशक 5 खिड़कियां इस काम के लिये खोली थी, लेकिन 4000 से अधिक छात्रों के लिये यह इन्तज़ाम काफ़ी नहीं था। इसलिये हर खिड़की पर छात्रों की मारा-मारी में सबसे ज़्यादा मुसीबत छात्राओं की थी क्योंकि उनके लिये कोई अलग से लाइन नहीं थी। अलग से लाइन हो भी नहीं सकती थी क्योंकि छात्र-छात्राओं के रोल नम्बर अलग से नहीं भेजे गये थे, सारे मिले-जुले थे।

यदि रोल नम्बर 5-7 दिन पहले आ गये होते तो सभी छात्र उन्हें आराम से ले सकते थे। देरी से आने का कारण यह बताया गया कि एम डी यू का सर्वर खराब हो गया था। विदित है कि अब रोल नम्बर डाक से न आकर कम्प्यूटर द्वारा ई-मेल से आते हैं। बेशक यह नई व्यवस्था, डाक व्यवस्था की अपेक्षा सस्ती, सरल तथा कम समय लेने वाली है परन्तु युनिवर्सिटी में चल रहे कुप्रबन्धन के चलते यह व्यवस्था भी कामयाब नहीं हो पा रही। इतना ही नहीं जिनको रोल नम्बर मिले भी उनमें से भी अनेकों के रोल नम्बरों में बहुत सी खामियां थीं। किसी का नाम ग़लत लिखा था तो किसी की श्रेणी ग़लत थी तो किसी के विषय ग़लत थे, तो किसी का सेंटर गलत था। अनेकों विद्यार्थी प्रिंसिपल के चक्कर इस बात के लिये काट रहे थे कि फ़ीस भरने के बावजूद उनका रोल नम्बर नहीं आया। यानी कुल मिला कर कॉलेज प्रिंसिपल एवं पूरे स्टाफ़ के लिये मुसीबत ही मुसीबत। इन सब गुटियों को एकत्र करके ई-मेल द्वारा एम डी यू को भेजने की प्रक्रिया भी साथ-साथ चल रही थी।

एम डी यू के बदइन्तजामी की कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि यहां से तो शुरू होती है, और यह किसी एक कॉलेज की नहीं बल्कि इससे जुड़े सभी कॉलेजों की है। जो तमाशा रोल नम्बरों में हुआ वही डेट शीट में होगा, फ़िर परीक्षा वाले दिन कभी प्रश्नपत्र नहीं पहुंचेगे, पहुंचेगे तो ग़लत पहुंच जायेंगे। उसके बाद उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी और अंत में मार्कशीट व सर्टिफ़िकेट में तरह-तरह की गड़बड़ियों की शिकायत हर साल बढ-चढ कर आना एक आम बात है। इन सब गड़बड़ियों को ठीक कराने के लिये छात्रों को खुद रोहतक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। गड़बड़ी करने वाले किसी बाबू के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही होना तो दूर बल्कि वे इन्हें ठीक करने के एवज में रिश्वत अलग से खाते हैं। बाबू रिश्वत क्यों न खायें जब सारा प्रशासन ही भ्रष्ट हो? हां यदि गड़बड़ी करने के लिये उत्तरदायी बाबुओं के विरुद्ध एक बार कड़ी कार्यवाही कर दी जाय तो अगली बार से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी में कमी जरूर होगी।

जनता की मुसीबत बना राजमार्ग चौड़ा करना

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर के बीच से गुज़रने वाले राजमार्ग नम्बर 2 को दिल्ली से आगरा तक चौड़ा करने का काम 6 वर्षों देरी से शुरू हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस काम का ठेका देश के एक बड़े एवं बदनाम कार्पोरेट रिलांयस इन्फ्रा (अनिल अम्बानी) को दिया हुआ है। इस कम्पनी का यह ठेका मैट्रो रेल प्रोजेक्ट से भी काफ़ी पहले दिया गया था। जबकि मैट्रो प्रोजेक्ट पूरा होने के कगार पर है और सड़क चौड़ाने का काम अब शुरू हुआ है। सड़क चौड़ाने के साथ-साथ तमाम मुख्य चौराहों पर ऊपरगामी पुल भी बनाये जा रहे हैं ताकि राजमार्ग का ट्रैफ़िक निर्बाध चलता रह सके।

रिलांयस कम्पनी की बदमाशी के चलते राजमार्ग का काम चलने वालों के लिये मुसीबत बना हुआ है। बल्लबगढ से लेकर सराय ख्वाज़ा तक के लगभग 20 किलोमीटर राजमार्ग पर जहां-तहां भी यह कम्पनी काम कर रही है, पूरी लापरवाही बरत रही है। सड़क सुरक्षा के तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए इसने राहगीरों की सुरक्षा को खतरे में डाला हुआ है। इसके अलावा जहां-जहां भी इसका काम चल रहा है वहां-वहां भयंकर जाम की स्थिति अलग बनी रहती है।

बल्लबगढ़ से दिल्ली जाते वक्त ओल्ड फ़रीदाबाद के चौक से पहले सड़क किनारे एक बड़ी खाई खोद कर छोड़ दी गई है, जो बहुत ही खतरनाक है, चौराहा पार करते ही सड़क एकदम संकरी हो जाती है। इसके लिये निर्माण कम्पनी को काम शुरू करने से पहले वहां सड़क को पर्याप्त रूप से चौड़ा करना चाहिये था। इसी तरह की अनेक खामियां एक सिरे से दूसरे सिरे तक मौजूद हैं।

ठेके में लिखी शर्तों के मुताबिक कम्पनी के लिये अनिवार्य है कि वह काम शुरू करने से पूर्व ट्रैफ़िक के निर्बाध परिचालन की व्यवस्था करे। अर्थात सड़क के जितने हिस्से को वह निर्माण कार्य के लिये अपने कब्ज़े में लेगी उतनी ही सड़क का निर्माण वह पहले करके देगी। इसके तहत कम्पनी ने बाटा मोड़ पर दिल्ली से बल्लबगढ़ जाने वाली सड़क का निर्माण तो किया लेकिन बस खाना पूर्ति के रूप में। जगह-जगह लापरवाही के साथ खामियां छोड़ गयी। कुछ अन्य स्थानों पर तो इतना भी नहीं किया गया है।

बल्लबगढ़ से दिल्ली जाते वक्त ओल्ड फ़रीदाबाद के चौक से पहले सड़क किनारे एक बड़ी खाई खोद कर छोड़ दी गई है, जो बहुत ही खतरनाक है, चौराहा पार करते ही सड़क एकदम संकरी हो जाती है। इसके लिये निर्माण कम्पनी को काम शुरू करने से पहले वहां सड़क को पर्याप्त रूप से चौड़ा करना चाहिये था। इसी तरह की अनेक खामियां एक सिरे से दूसरे सिरे तक मौजूद हैं।

इसके अलावा ट्रैफ़िक पुलिस की कोताही के चलते सड़क किनारों पर होने वाली पार्किंग ने आवागमन को और भी कष्टदायक बना दिया है।